

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

- 03 भाजपा के दो बार के पार्षद वरिष्ठ नेता बीबी सिंह हुए 'आप' में शामिल
- 06 बुजुर्गों की उपेक्षा करके हम स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते
- 08 हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले, कनाडा को पीएम मोदी का सख्त संदेश

आपके पास है 10 मिनट या खर्च करना चाहते हैं 10,000 रुपये? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बचा सकती है मोटी रकम

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर जहरीला हो गया है। देश की राजधानी में AQI यानी वायु-गुणवत्ता सूचकांक को बिगाड़ने में कई वजहें अपना योगदान करती हैं। लेकिन यहाँ अक्सर दोष का एक बड़ा वाहनों के मध्ये मढ़ा जाता है। इंजन से चलने वाले वाहनों से होने वाले टेलपाइप उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ अनुमेय सीमाएं हैं जिन्हें प्रदूषण-नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्रों द्वारा अनुमोदित किया जाता है जो सभी के लिए अनिवार्य हैं।



प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में सिर्फ दो हफ्तों में 54,000 से ज्यादा वाहनों पर PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) (पीयूसी) सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के कारण जुर्माना लगाया गया। शहर में अधिकारी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कस रहे हैं। इसलिए अब यह जांचने का सही समय है कि आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र है या नहीं। यह एक ऐसा कदम है जो आपके काफी पैसे बचा सकता है।

वाले किसी भी वाहन के लिए जुर्माना 10,000 रुपये तक है। कुछ स्थितियों में वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। और बार-बार अपराध करने जैसी सबसे खराब स्थिति में वाहन के मालिक को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है।

वैध पीयूसी कैसे हासिल करें?
पीयूसी हासिल करने के लिए बहुत कम प्रयास और समय की जरूरत होती है। और निश्चित रूप से, यह आपको पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना भरने की परेशानी से बचा सकता है। दिल्ली और अन्य जगहों पर भी बहुत सारे पीयूसी केंद्र हैं। किसी भी पीयूसी सेंटर में चले जाएं, अपना मोबाइल नंबर साझा करें, ओटीपी आने पर सेंटर को दे और आपका पीयूसी बन जाएगा।

एक बार जब आपको वैध पीयूसी मिल जाता है, तो आपको एक चेकिंग शुल्क देना पड़ता है। यह आम तौर पर निजी कारों के लिए लगभग 150 रुपये और निजी दोपहिया वाहनों के लिए 100 रुपये होता है। पीयूसी आमतौर पर वाहन की जांच के समय से एक वर्ष के लिए वैध होता है।

क्या आपका वाहन पीयूसी परीक्षण में फेल हो सकता है?
अगर टेलपाइप उत्सर्जन अनुमेय सीमा से ज्यादा है, तो वाहन जांच में फेल हो जाएगा। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है और परीक्षण शुल्क का भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, यह उस वाहन के मालिक पर निर्भर करता है कि वह इसके कारण का पता लगाने और उसे ठीक

करने के लिए वाहन की जांच सर्विस सेंटर पर करवाएं।
क्या होती है इसकी वजह
टेलपाइप उत्सर्जन कई कारणों से ज्यादा हो सकता है। जिसमें गंदे फ्यूल इंजेक्टर, दोषपूर्ण इग्निशन सिस्टम और खराब स्पार्क प्लग से लेकर दोषपूर्ण ऑक्सीजन सेंसर तक शामिल हैं। यह भी ध्यान रखें कि वाहन के साइलेंसर को कोई भी नुकसान होने पर वाहन पीयूसी जांच में फेल हो जाएगा।
यह दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि अगर कोई वाहन पीयूसी जांच में फेल रहता है, तो उसे पूरी जांच और मरम्मत के लिए किसी प्रमाणित सर्विस सेंटर में ले जाया जाए।

टोलवा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website: www.tolwa.in
Email: tolwadethi@gmail.com
bathlajaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उधम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समायपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर बन रहा रिवर्सल प्लेटफार्म, बढेंगे मेट्रो के फेरे



दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने काम शुरू करवाया, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पूरा कराने का लक्ष्य
मई से उपयोग में लाया जा सकेगा, 140 मीटर लंबा होगा ट्रैक परिवहन विशेष न्यूज

बचत का उपयोग मेट्रो कॉरपोरेशन ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए कर सकेगा। वहीं, यात्रियों को भी सहायिता होगी। मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से बताया गया कि यह ट्रैक करीब 140 मीटर लंबा होगा। अप्रैल के अंत में इसका निर्माण पूरा कर मई से उपयोग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन का मौजूदा समय में टर्मिनल स्टेशन है। यहां पर नोएडा के सेक्टर-62, 63 के संस्थानों में नौकरी के लिए आने वाले लोग वाजियाबाद की बड़ी आबादी मेट्रो से जुड़ती है। इसके साथ ही नेशनल हाइवे पर बस के जरिए आने वाले लोग जिनका गंतव्य ब्लू लाइन मेट्रो के आस-पास रहता है वह भी आते जाते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां पर यात्रियों की भीड़ रहती है। अभी स्थिति यह थी कि इस स्टेशन का एक ही प्लेटफार्म

दिल्ली के फेमस ब्रिज पर फिर मंडराया खतरा एएसआई ने पीडब्ल्यूडी से मांगी मदद; 150 साल पहले हुआ था निर्माण

दिल्ली के मंगी ब्रिज के फिर से क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। ऊंचे वाहन ब्रिज की आर्च से टकरा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के प्रयास विफल रहे हैं। एएसआई ने लोक निर्माण विभाग से मदद मांगी है। ब्रिज के नीचे और आसपास सड़क का तल कम से कम चार फीट नीचे किए जाने की मांग की गई है।



नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मंगी ब्रिज के फिर से क्षतिग्रस्त हो जाने का खतरा बढ़ गया है। लालकिला के पीछे रिंग रोड पर स्थित कुछ समय पहले मरम्मत की गई इस ब्रिज की दाहिनी आर्च से फिर से ऊंचे वाहन गुजर रहे हैं। ऊंचे वाहन आर्च से टकरा रहे हैं।

वहीं, इस फेमस ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने का खतरा बढ़ने से लोगों की जान को भी खतरा बढ़ गया है। अब लोग इसके नीचे से निकलने से भी डर रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग से मांगी है मदद
बताया गया कि ब्रिज की इस आर्च को वाहनों से टकराने से बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सभी प्रयास फेल हो गए हैं। क्योंकि ऊंचे वाहनों को इस आर्च से गुजरने से रोकने के लिए ब्रिज के पास लगाया गया हाइट बैरियर एक माह में दो बार टूट चुका है।

अब इस ब्रिज के नीचे और आसपास सड़क का तल कम से कम चार फीट नीचे किए जाने के लिए एएसआई ने लोक निर्माण विभाग से मदद मांगी है, इसे लेकर एएसआई ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है।
जर्जर हालत में पहुंच चुके मंगी ब्रिज को बचाने की कोशिश
जर्जर हालत में पहुंच चुके मंगी ब्रिज को बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने एक साल काम शुरू किया था। जिसके तहत ब्रिज के नीचे के भाग में मजबूती दी गई थी। इसके लिए

आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। ब्रिज के नीचे की तरफ क्षतिग्रस्त भाग को तैयार करने में स्टील के अर्ध चंद्राकार गार्डर डाले गए हैं। इसी तकनीक पर 2010 में इसी ब्रिज की बाईं आर्च को बचाया गया था।
यह बैरियर दो बार टूट चुका
एएसआई ने योजना के तहत ब्रिज के इस लेन से ऊंचे वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिज से कुछ दूरी पर पहले ऊंचे हाइट बैरियर लगा दिया था। मगर ट्रकों द्वारा टक्कर मार दिए जाने से

पिछले एक माह में यह बैरियर दो बार टूट चुका है। इस समय भी यह टूटा पड़ा है।
150 वर्ष पूर्व किया गया था इस ब्रिज का निर्माण
लालकिला के पीछे स्थित इस ब्रिज का निर्माण 150 वर्ष पूर्व किया गया था। इसका प्रयोग लालकिला से सलीमगढ़ किले में जाने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इस ऐतिहासिक ब्रिज के नीचे से रिंग रोड गुजरता है। पुराना हो जाने से इस ब्रिज के ऊपर से कुछ साल से वाहनों का आवागमन बंद है।

कालका-शिमला ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने के लिए सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से यूनेस्को विश्व धरोहर कालका-शिमला रेललाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है।
परिवहन विशेष न्यूज

सुदृढ़ किया जा रहा है।
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर होगा काम: सीएम
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश अपनी वर्तमान 1,500 मिलियन यूनिट थर्मल पावर खपत को हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य 13,500 मिलियन यूनिट बिजली की खपत करता है जिसकी एक बड़ी आपूर्ति पहले से ही नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होती है। बिजली वितरण तंत्र में 90 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा खपत प्राप्त करने से हिमाचल को देश के पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा राज्य के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और एक वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना है। इससे प्रदेश के उद्योगों को 'इको मार्क' के लिए आवेदन करने की भी अनुमति भी मिल सकेगी, जिससे उनके उत्पादों की मूल्य में वृद्धि होगी।



ग्रीन पंचायत योजना शुरू की: सुक्खू
उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत अगले चार से पांच वर्षों में 2,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दो वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना हो गया है, जो प्रदेश सरकार की स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने

कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की विकेंद्रीकरण पहल के तहत ग्रीन पंचायत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर 500 किलोवाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े ग्रांड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बिजली की बिक्री से होने वाली आय का उपयोग पर्यावरण अनुकूल और सत विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
1,500 बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा

उन्होंने कहा कि राज्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के सहयोग से इस सुविधा का काम चल रहा है और इस तरह की अन्य सुविधाओं के लिए निजी निवेशकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की 3,200 बसों के बेड़े में से 1,500 बसों को आगामी दो से तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा रहा है। सरकार के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों के बेड़े को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है।
छह एनएच को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा

इसके अतिरिक्त, छह प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को ई-वाहनों के संचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी और बसें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, इससे सरकारी सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल वाहनों का संचालन सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से नए उद्योगों या मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए सख्त मानक संचालन प्रणाली को लागू कर सभी प्रस्तावों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है।



सांसों पर संकट! AQI पहुंचा 368 के पार, आंखों में जलन से गाजियाबाद के लोगों का बुरा हाल

दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई बढ़ने से लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। वहीं गाजियाबाद जिले में लोनी और वसुंधरा रेड जोन में पहुंच गए हैं। बताया गया कि लोनी का एक्यूआई सर्वाधिक 369 दर्ज किया गया जबकि वसुंधरा का AQI 312 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के ये दोनों सेंटर रेड जोन में बने रहे। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

परिवहन विशेष न्यूज़

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिले के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई AQI) सोमवार को 295 दर्ज किया गया। जिले में लोनी का एक्यूआई (Air Quality Index) सर्वाधिक 369 और वसुंधरा का एक्यूआई 312 दर्ज किया गया। ये दोनों सेंटर रेड जोन में बने रहे। एक्यूआई में इजाफा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोनी के हालात खराब
जिले में ग्रेप (ग्रेड) रेखांकन एक्शन प्लान लागू होने के बाद से ही हवा केवल एक दिन ही मध्यम श्रेणी में रही है। बाकी दिन खराब व बेहद खराब दर्ज की गई है। लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार को 353 दर्ज किया गया।

प्रदूषण के कारण आंखों में जलन
वहीं, संजयनगर, इंदिरापुरम व वसुंधरा के मुकाबले सबसे खराब रही। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन रही। लोनी में अल्ट्रा फैंक्टोरियों के संचालन को प्रदूषण का मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं, इंदिरापुरम व संजय नगर में सड़कों पर उड़ती धूल को अधिकारी प्रदूषण का कारण मान रहे हैं।

लोगों का क्या कहना...
लोगों का कहना है कि अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यही स्थिति रही तो हवा जल्द ही गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी। अभी से ही सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन होने लगी है। खुले में बिकरही निर्माण सामग्री

गाजियाबाद शहर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख बदली, जानिए कब पढ़ेंगे वोट और रिजल्ट आने की डेट

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव अब 20 नवंबर को होगा मतदान और 23 नवंबर को आगुा परिणाम। जानिए इस सीट पर कितने मतदाता हैं कौन-कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं और किन पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के प्रचार की भी पूरी जानकारी।

भारत निर्वाचन आयोग ने तीन राज्यों की कुछ सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बदलाव किया है। इसमें उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट के अलावा नौ अन्य विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। पहले ये उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएंगे। वहीं, चुनावों का परिणाम 23 नवंबर को ही आएगा।

गाजियाबाद सीट पर साढ़े 4 लाख से ज्यादा मतदाता

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कुल 4.63 लाख मतदाता हैं। इनमें प्रमुख रूप से अनुसूचित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या

विडंबना देखिए कि जहां हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वहीं देश की 67.4 फीसदी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से भी ज्यादा है।

देश में सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी लाचार और बीमार रही है। दिल्ली का हाल ए दिल् किसी को दिखाई नहीं दिया। राजनीतिक दलों ने भीषण प्रदूषण के संकट से जूझ रही दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस जानलेवा समस्या से निजात दिलाने के बजाए एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने का काम किया है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में उठाए गए कदम अभी तक कंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के प्रदूषण के सामने सरकारों की लुंजलुंज नीति के आगे परत नजर आता है। दर्जनों बार चेताना देने के बावजूद केंद्र और दिल्ली राज्य की सरकार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती दिखती हैं। कहने को देश विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व स्तर पर रैंकट साइड सहित कई क्षेत्रों में भारत ने झंडे गाड़े हैं, किन्तु देश की राजधानी प्रदूषण के मामले में विश्व में बदनाम है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिलसिले में सुनवाई के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान एक बार फिर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पंजाब ने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह पहली बार नहीं है जब पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई हो, हर साल सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सांस तक लेना दुभर हो

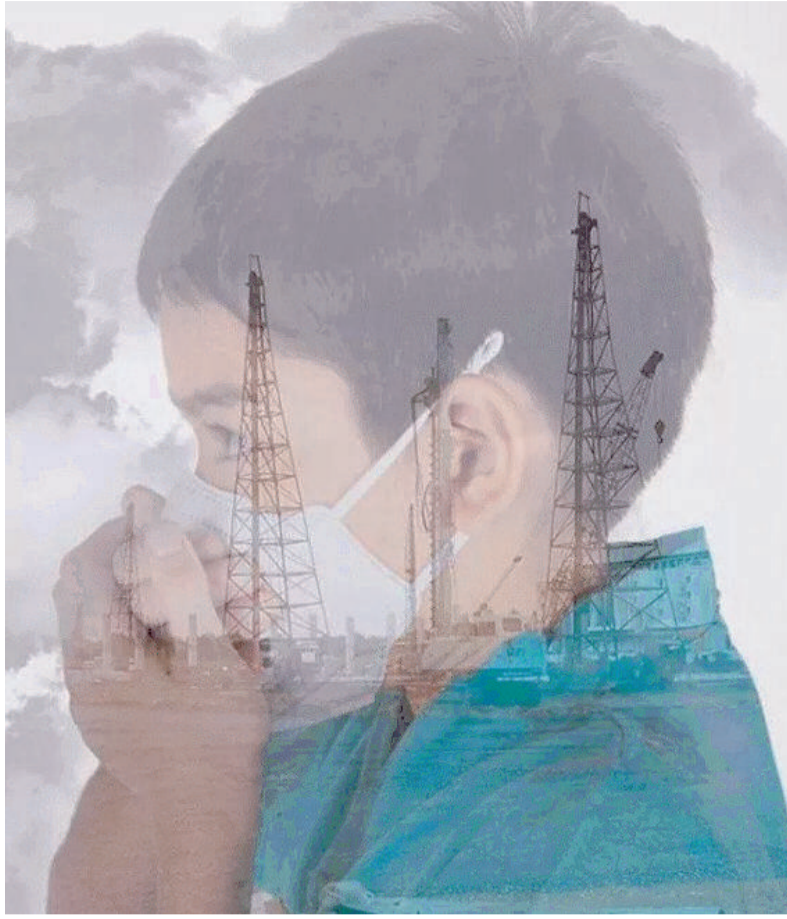
●●●●●

जगह-जगह खुले में निर्माण सामग्री बिक रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन पर कार्रवाई के नाम पर खानापूरी की जा रही है। कूड़े में आग लगाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। रविवार को हिंडन नहर रोड सहित विभिन्न स्थानों पर कूड़े में आग लगती मिली। कूड़े में आग लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर लोग चिंता में हैं। वहीं, आगे सर्दी बढ़ने से अभी मौसम में और बदलाव आएगा। अब धीरे-धीरे स्मॉग भी बढ़ने लगेगा। इससे लोगों को और ज्यादा दिक्कत होगी। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है।

रविवार को स्टेशनों का एक्यूआई
स्टेशन - एक्यूआई
इंदिरापुरम - 269
लोनी - 353
संजय नगर - 246
वसुंधरा - 312
स्टेशन एक्यूआई
इंदिरापुरम 269
लोनी 353
संजय नगर 246
वसुंधरा 312

प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमारी टीम जगह-जगह प्रतिदिन निरीक्षण करती है। खुले में निर्माण सामग्री बेचने और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। - विकास मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी



वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जिला जज को बर्खास्त करने की मांग

गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वकील जिला जज को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को जिला जज कोर्ट रूम में जमानत के मामले को लेकर वकीलों और जिला जज के बीच हुई नोकझोंक के बाद पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इसके बाद से ही वकीलों में आक्रोश है।

गाजियाबाद। जिला जज कोर्ट रूम में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का धरना चल रहा है। आज से अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। मंगलवार को जिला जज कोर्ट में जमानत के मामले की पहली सुनवाई को लेकर वकीलों और जिला जज अनिल कुमार के बीच शुरू हुई नोकझोंक के बाद पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था। उसके बाद से ही वकीलों में आक्रोश है। दीवाली की छुट्टियों के बाद आज कोर्ट खुली है, लेकिन वकील हड़ताल पर हैं। वकील किसी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट खुली है और न्यायिक अधिकारी भी बैठे हुए हैं। लेकिन वकील कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट में अपने मामलों में आने वाले वादकारियों को तारीख मिल रही है।
वार अध्यक्ष ने कहा-
अनिश्चितकालीन है हड़ताल
वार अध्यक्ष दीपक शर्मा का कहना है कि वकीलों की हड़ताल उनकी मांग माने जाने



तक जारी रहेगी। बार काउंसिल की समिति से उन्होंने मांग की है कि जिला जज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाठीचार्ज में घायल वकीलों को मुआवजा मिले और वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
हाइकोर्ट में याचिका दाखिल
बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा ने वकीलों की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उनका

कहना है कि जो मांग उन्होंने बार काउंसिल के समक्ष रखी है उन्हीं मांगों को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
कई जिलों से मिल रहा समर्थन
गाजियाबाद के वकीलों को प्रदेश के कई जिलों की बार एसोसिएशन से समर्थन मिल रहा है। सोमवार को आगरा और ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया।
वकीलों की हड़ताल कब तक रहेगी ?
वार अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि

गाजियाबाद के जिला जज का तबादला व उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों का तबादला और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा इस प्रकरण में अधिवक्ताओं पर दर्ज दोनों एफआईआर को खारिज किया जाए और कोर्टिल अधिवक्ताओं दो-दो लाख रुपये मुआवजा राशि दी जाए। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया जाएगा।

राजनीतिक दलों के एजेडे में नहीं है दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण

योगेंद्र योगी

विडंबना देखिए कि जहां हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वहीं देश की 67.4 फीसदी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से भी ज्यादा है।

देश में सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी लाचार और बीमार रही है। दिल्ली का हाल ए दिल् किसी को दिखाई नहीं दिया। राजनीतिक दलों ने भीषण प्रदूषण के संकट से जूझ रही दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस जानलेवा समस्या से निजात दिलाने के बजाए एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने का काम किया है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में उठाए गए कदम अभी तक कंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के प्रदूषण के सामने सरकारों की लुंजलुंज नीति के आगे परत नजर आता है। दर्जनों बार चेताना देने के बावजूद केंद्र और दिल्ली राज्य की सरकार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती दिखती हैं। कहने को देश विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व स्तर पर रैंकट साइड सहित कई क्षेत्रों में भारत ने झंडे गाड़े हैं, किन्तु देश की राजधानी प्रदूषण के मामले में विश्व में बदनाम है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिलसिले में सुनवाई के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान एक बार फिर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पंजाब ने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह पहली बार नहीं है जब पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई हो, हर साल सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सांस तक लेना दुभर हो

●●●●●

जाता है। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दिल्ली देश का 8वां प्रदूषित शहर था, वहीं बार्नहार्ट के बाद बिहार का बेगूसराय देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद एनसीआर का ग्रेटर नोएडा शामिल था। दिल्ली और फरीदाबाद ही नहीं देश के कई अन्य छोटे बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता जानलेवा बनी हुई है। देश में प्रदूषण की स्थिति किस कदर भयावह है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में पीएम 2.5 हर साल दो लाख से ज्यादा अजन्मों को गर्भ में मार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर जो गुणवत्ता मानक तय किए हैं उनके आधार पर देखें तो देश की सारी आबादी यानी 130 करोड़ भारतीय आज ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो उन्हें हर पल बीमार बना रही है, जिसका सीधा असर उनकी आयु और जीवन गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

विडंबना देखिए कि जहां हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वहीं देश की 67.4 फीसदी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से भी ज्यादा है। यदि हर भारतीय साफ हवा में सांस ले तो उससे जीवन के औसतन 5.3 साल बढ़ सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली-एनसीआर में से लगभग 50 प्रतिशत भारत में दर्ज की गई हैं, और उसके बाद चीन और बांग्लादेश आते हैं। वर्ष 2022 में अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, प्रशांत महासागर की तरफ कैलिफोर्निया में, पीएम 2.5 नामक वायु प्रदूषक और भीषण गर्मी दोनों के अत्यंतकालिक संघर्ष से जान जाने का खतरा बढ़ा है। यह समस्या पहले से ही भारत में मानव स्वास्थ्य

●●●●●



के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बनी हुई है, जहाँ पीएम 2.5 प्रदूषण ने औसत अनुमानित जीवन-काल को 5.3 वर्ष कम कर दिया है।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) में प्रकाशित एक नई रिसर्च के मुताबिक घरो, इमारतों से बाहर वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण भारत में हर साल 21.8 लाख जिंदगियों को छीन रहा है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां वायु प्रदूषण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियों को छीन रहा है। तुनिया भर में 2019 के दौरान सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण के चलते 83.4 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो गई थी। इसके लिए प्रदूषण के प्रमाणात और ओजोन जैसे प्रदूषक जिम्मेवार थे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2019 की तुलना में 2020 में भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ

●●●●●

है। हालांकि, इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा उत्साहजनक बात नहीं है क्योंकि वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद भारत के 22 शहर दुनिया के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में लोगों के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जो हर साल लगभग 7 मिलियन असायुक्त मौतों का कारण बनता है। इनमें से 600,000 मौतें बच्चों की होती हैं।
भारत में वायु प्रदूषण की वजह से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारतीय व्यापार जगत को करीब 95 बिलियन अमरीकी डॉलर (7 लाख करोड़) का नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि भारत की कुल जीडीपी का करीब 3 प्रतिशत है। यह नुकसान सालाना कर संग्रह के 50 प्रतिशत के बराबर है या भारत के स्वास्थ्य बजट का डेढ़ गुना है। डलबर्ग

●●●●●

एडवाइजंस और भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) की क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। डलबर्ग का अनुमान है कि भारत के कामगार अपने स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के कारण प्रति वर्ष 130 करोड़ (1.3 बिलियन) कार्यदिवसों को छुट्टी लेते हैं जिसके 6 बिलियन अमरीकी डॉलर के राजस्व का नुकसान होता है। प्रदूषण से स्वास्थ्य और भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद सत्तारूढ़ दलों की प्राथमिकता इसे समाप्त करना नहीं है। चुनावों के दौरान अदृश्य दिखने वाले सर्वाधिक खतरनाक इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल मौन रहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के घोषण पत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयासों का स्थान नहीं मिलता। यदि राजनीतिक दल इसी तरह प्रदूषण के हालात की उपेक्षा करते रहे तो वे दिन दूर नहीं जब भारत विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के सौपान तय करने के बावजूद विश्व में पिछड़ा नजर आएगा।

●●●●●

विडंबना देखिए कि जहां हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वहीं देश की 67.4 फीसदी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से भी ज्यादा है। यदि हर भारतीय साफ हवा में सांस ले तो उससे जीवन के औसतन 5.3 साल बढ़ सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिलेगा जहां रहने वाले हर इंसान की आयु में औसतन 11.9 वर्षों का इजाफा हो सकता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार ओजोन संबंधी सभी मौतों में से लगभग 50 प्रतिशत भारत में दर्ज की गई हैं, और उसके बाद चीन और बांग्लादेश आते हैं। वर्ष 2022 में अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, प्रशांत महासागर की तरफ कैलिफोर्निया में, पीएम 2.5 नामक वायु प्रदूषक और भीषण गर्मी दोनों के अत्यंतकालिक संघर्ष से जान जाने का खतरा बढ़ा है। यह समस्या पहले से ही भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बनी हुई है, जहाँ पीएम 2.5 प्रदूषण ने औसत अनुमानित जीवन-काल को 5.3 वर्ष कम कर दिया है।

●●●●●

